साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 29 | प्रति सोमवार इंदौर, 19 फरवरी से 25 फरवरी 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

राष्ट्र शत्रुओं को कालीन, जनता पर हवाई हमलों से आंसू

देश के अन्नदाताओं पर 56 इंच की लाल आंखें

अपनी पूंजी मित्रों के लिए कानून का डंडा कब तक जनता को भिखारी बना चलाओगे?

पंजाब और हरियाणा के किसान अपने फसलों की एमएसपी के लिए सरकार सम्मान करने दिल्ली में एकत्रित होने के लिए कोई ट्रैक्टरों से जाने वालों के रास्तों पर कीलें कंक्रीट की दीवाल बनाने के साथ एकत्रित होने पर उन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसा आंसू बांट रही है।

जब तक मोदी सत्ता में नहीं आया थातो चीन और पाकिस्तान के घुसपैठ पर मनमोहनसिंह को लाल आंखें दिखाने के लिए ललकारता था। अब जब से सत्ता में आया है तो चीन से मोटा कमीशन खाकर देश के उद्योग धंधों पर भारी भरकम टैक्स ठोक उन्हें खत्म करवा दिया और अब चीनी कंपनियां और चीनी मालपूरे भारत के बाजारों में जाते हैं। जनता को चीनी माल खरीदने के लिएमना किया जाता हैउसको शत्रु बताया जाता है परंतु वह शत्रुने भारत की सीमाओं पर अपनी कॉलोनियां काट न केवल गांव और शहर बसा लिए वर्णन आक्रमण होने पर उसने भारत की सीमाओं में लद्दाख से लेकर म्यांमार तक सड़के उद्योग बंकर खड़े कर दिए अब चीनी प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल लाल लाल आंख दिखाने की औकात नहीं हो रही। भाई हाल पाकिस्तान का भी है बेशक दहशत फैलाने फिर छोटे-मोटे अपराधों के निरीहों को पकड़ने के बाद कुछ दिन जेल में रखकर चुपचाप रात के अंधेरे में पुलिस की गाड़ियों में बैठकर जंगलों में दौड़ाते हुए गोली मार दी जाती है और बहादुरी दिखाई जाती है कि हमने इतने आतंकी मार दिए, जबकि असली आतंकियों को जानबूझकर पालते और उनसे ही आक्रमण करने की पुलिस और मिलिट्री के कैंपों परिसरों में आतंकी घटनाएं करवाई जाती है तो वहां तो गृहमंत्री तड़ीपार अमित शाह की औकात नहीं होती कि उनको रोक सके परंतु पिछले 10 दिनों से देश में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों पर देश के शत्रुओं की तरह ड्रोन से हवाई हमलों में आंसू गैस के गले अवश्य बरसाई जा रही है।

बेशक किसीदो हम लोग को नाकाम करने के लिएजो पतंग उड़ा कर उसमें ड्रोन को उलझा कर गिरने का जो खेल खेल उसे न केवल देश के बल्कि दुनिया के देशों की सेना की आर्मामेंट टैक्टिकल के लोग भी चकित हैं।

25 फरवरी 2022: रूस-यूक्रेन युद्ध को 2 साल...

विश्व का सबसे बड़ा शैतान अमेरिका युद्धों में क्यों डाल रहा घी...

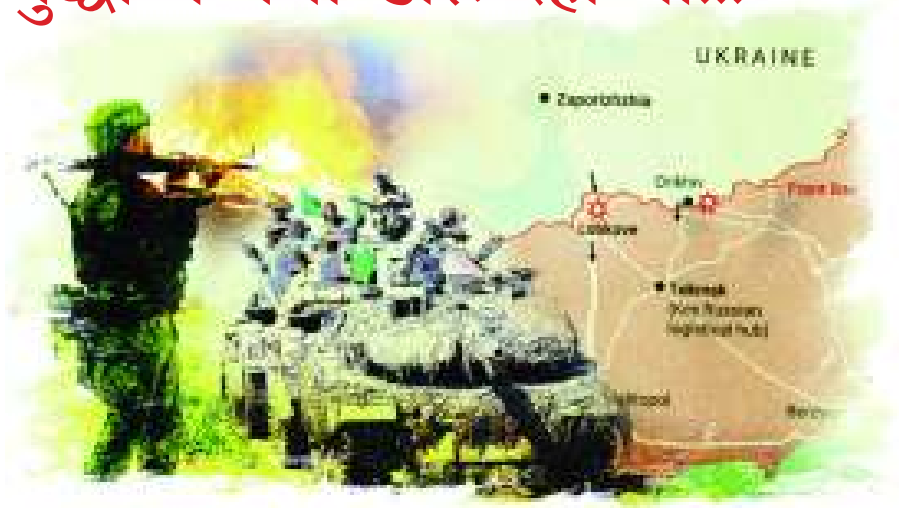

अमेरिकी हथियार उत्पादकों के लिए हर युद्ध कमाई व विक्रय संवर्धन का हिस्सा

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय हथियार यथा लाइट मशीन गन मिसाइलें टैंकों से लेकर अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें गोला बारूद तोपें लड़ाकू विमान पनडुब्बियां समुद्री युद्धक नौकायें जहाज रडार उत्पादक कंपनियां इतिहास में पूरे अमेरिका की सरकार को चलाती वहां पर अपने मनमर्जी के शासक बैठा अपने फायदे के लिए कानून बनवाती नीतियां निर्धारित करती हैं। (शेष पेज 7 पर)

मप्र सरकार का अंतरिम बजट 2024

क्या जुलाई के बाद नई सरकार बनेगी?

जनधन का लूटा मोटे कमीशन के लिए अधोसंरचना पर खर्च

आखिर अंतरिम बजट क्यों? वेतन के लिए धन नहीं, 50 से 80% कमीशन के लिए 4 गुनी से 10 गुनी तक डीपीआर

प्रदेश में 15 फरवरी को ही इस बार बजट पेश कर दिया गया जो फरवरी के अंतिम दिन वर्तमान व अगले वर्ष का प्रस्तुत करने की परंपरा रही है। पर भाजपा की परंपरा के अनुकूल की कोई भी सत्र अपने भ्रष्टाचार, नाकामियों बढ़ते अपराधों को छुपाने के लिए उस पर बहस और हंगामा न हो समय से पहले ही आवश्यक काम कर और प्रश्नोत्तर का जवाब ना देना पड़े पूरा कर दिया जाता है। (शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

सरकारी नौकरी मतलब गुलामी नहीं

खाद कर्मचारी अधिकारी को न्याय और कानून की आवाज उठाने का हक

लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकारी नौकरी में कर्मचारियों-अधिकारियों को जनता से वसूले धन से नियमो कानूनों का पालन कर ईमानदारी से जन कल्याण कारी कार्यों को समय पर समय से संपन्न करने के लिए वेतन दिया जाता है। तो हर सरकारी कर्मचारी अधिकारी को हर गलत गैर कानूनी जन हितों के विरुद्ध काम करने भ्रष्टाचार बेईमानी जालसाजी के लिए उसका व्यक्तिगत दायित्व है कि वह उसको रोके और हर संभावित कार्यवाही शिकायत सूचना अपने वरिष्ठों को देना सुनने या ऐसे कृत्यों के पालन करने में वरिष्ठों के मूक सहयोग पर न्यायालय की शरण ले। और ऐसे कार्यों को करने से साफ मना कर दें। और दस्तावेज रिकॉर्ड साक्ष्य एकत्रित कर समाचार पत्रों में उन भ्रष्टाचार लूट डकैती जालसाजीयों को प्रकाशित कर जनता को बता उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और यह यह गैर कानूनी और गोपनीयता भंग करने की अपेक्षा राष्ट्रीय हित चिंतन में ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों को वह किसी भी विभाग के किसी भी पद निमित्त दैनिक वेतन भोगी संविदाया ठेका कर्मी ही क्यों ना हों। सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। बेशक रोजी रोटी और जीवन यापन की व्यवस्था पर वरिष्ठ भ्रष्ट न केवल अपने प्रभाव का दुरुपयोग करउन्हें नौकरी से हटाने की चालें चलेंगे? व चलते हैं।

बेशक बहुराष्ट्रीय कंपनियां सत्ताधीश प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रालयों में बैठे मंत्रियों और भ्रष्ट जालसाज भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों को खरीद मोटा पैसा बांट अपने हिसाब से नीचा कर राष्ट्र व राष्ट्र की जनता खेतों के विरुद्ध देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं परंतु कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसके विरुद्ध आवाज उठाने में अपने स्वार्थों, मोटी कमाई सुविधाओं के लालच के कारण सच बोलने और आवाज उठाने में आगे आने को तैयार नहीं फिर जब देश का प्रधानमंत्री ही घोर जाहिल भ्रष्ट जालसाजों हो, और अपनी छल बल दल के दम पर देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर नीचे तक के सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों व उनके निर्णयों को को अपने तरीके से हांक निर्देशित कर रहा हो। तो समझा जा सकता है कि यहां पर न्याय कानून नियम सब जालसाज सत्ताधीशों की कठपुतली बन देश व देश की जनता की बर्बादी में जुटे हुए हैं। हाल ही में जो पंजाब-हरियाणा में किसानों का फसलों की न्यूनतम सहयोग कीमत या मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर आंदोलन चल रहा है जिसे रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग तोठीक था पर उनको रोकने के लिए शत्रुओं की भांति दिल्ली की पुलिस ने जो सड़कों पर किले गाड़ने कांक्रीट की दीवार उठाने गड्ढे करने का कृत्य किया। वह पूर्णताः अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। पर इसके लिए अपराधिक प्रवृत्ति का तड़ीपार गृहमंत्री अमित शाह अकेला ही जिम्मेदार नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार का गृह सचिव के साथ आईजी डीजी से लेकर गड्ढा खोदने वाले और कंक्रीट की दीवार खड़ा करने सड़कों पर कीलें गाड़ने उन पर ड्रोन से हवाई हमले करने टियरबम बरसाने वॉल्यूम पुलिस के कर्मचारी अधिकारी से लेकर मजदूर तक अपनी ही जनता पर जुर्म ढाने वाले सभी जिम्मेदार हैं। आखिर सब इतने निष्ठुर स्वार्थी मक्कार कैसे और क्यों हो गए जिन्हें वह किस जून का न जाता है उनके भोजन की व्यवस्था करता है और अपने ही देश का नागरिक हैं उसे पर यह जुल्म करने वालों में भारतीय प्राताड़ना सेवा अधिकारी से लेकर भारतीय क्राइम प्रोटेक्शन सर्विस अधिकारियों में नियम कानून देशभक्ति हीन भावना के चलते किसी का भी ना तो स्वाभिमान जगा न दया रहम, हमारा जन्म इसलिए तो नहीं हुआ कि हम निर्दोषों पर भी गुलामों की भांति अपने जीवनयापन, स्वार्थ के लिए अकारण ही शत्रुता पूर्ण तरीके से अपनी ही जनता का रक्त बहायें उनकी उनकी उचित मांगों को सुनने आश्वासन देने और निराकरण करने में भी यदि सत्ताधीश सक्षम नहीं तो ऐसी अमानवीए अत्याचार करने की अपेक्षा सत्ता छोड़ते क्यों नहीं?

मप्र गृह निर्माण मंडल भ्रष्टों जालसाजों का अड्डा

कॉलोनी बेंच दी, रखरखाव नगर निगम के हवाले

तोड़ने बनाने का हक कैसे? क्या मोटी कमाई का षड्यंत्र

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मधु संरचना विकास मंडल, प्रधान सचिव आयुक्त से लेकर नीचे उप यंत्री संपदा प्रबंधक तक वर्तमान में पुराने सरकारी कार्यालयों जमीनों के साथ अपने ही बनाए कमजोर मकानों बहु मंजिला निम्न आय भवनों को तोड़कर पुनः बनाने काजूस षड्यंत्र कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है इसकी डीपीआर बनाने से लेकर स्वीकृति निविदा निकालना स्वीकृत करने में कमीशन खोरी करने के साथ डीपीआर के हिसाब से मिट्टी परीक्षण खुदाई बेसमेंट फाउंडेशन स्ट्रेटा टेस्ट निर्माण कार्य प्रारंभ होने निरीक्षण करने सिमेंट ईंट गिट्टी लोहे की छड़ें की गुणवत्ता आकर और मात्रा में समझौता करने के बदले फिर समय विस्तार महंगाई स्वीकृत करने मे भी प्रतिशत के हिसाब से वसूली करने का षड्यंत्रकार्य प्रारंभ के बाद से ही शुरू हो जाता है बेशक यह सारा खेलहर निर्माण कार्य करने वाले विभाग तथा लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, ग्रामीण यंत्रिकीय, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण समय खुलकर किया जाता है। यही कारण है कि पिछले 18 सालों में यह सारी जानकारियां जो धारा 4 के अंतर्गत 25 बिंदुओं की जानकारी जिसमें कार्य की मांग डीपीआर लागत निविदा लगाने प्राप्त होने इसकी स्वीकृति का आधार स्वीकृत निविदाकार को उसका कार्यादेश जारी करने आदि सब अपने विभागों की साइट पर नाप पुस्तिका और बिल भुगतान से लेकर पूजा प्रमाण पत्र तक सब साइट पर अपलोड किया जाना चाहिए इसके साथ ही हर साइट पर जहां सड़क भवन पुल नहरें तालाब आदि का निर्माण किया जा रहा है उसकी कुल लागत लंबाई चौड़ाई नक्शा आदि सब की जानकारी निर्माण स्थल पर सूचना पटल पर लगाई जानी चाहिए पहले ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण हर सड़क पर लगता था पर उसने भी लगाना बंद कर दिए हैं जो पूर्णता गैरकानूनी है और यही आधार है जिसमें यह भ्रष्टाचार करते रहते हैं दूसरी तरफ ग्रैंड मॉल मंडल ने जो मकान बनाए थे उसके रख-रखाव लिपाई पुताई मरम्मत आदि का सारा पैसा वहां बैठे उप से लेकर सहायक, कार्यपालन यंत्री तक कागजों में ही स्वीकृत करके ही सारा पैसा हजम कर जाते हैं। इस प्रकार जानबूझकर भावनाओं को पहले कमजोर किया जाता है और उसके बाद में षडयंत्र पूर्वक तरीके से उसको जर्जर बनाकर पुनः तोड़ने बनाने और मोटी कमाई करने का शरण दर किया जाता है जैसा की इंदौर केलिक चौराहे पर स्थित और नेहरू नगर के 676 क्वार्टर्स को तोड़कर पुनः बनाने के षड़यंत्र में किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गृह निर्माण मंडल के स्थानीय कार्यालयों ने यह फ्लैट्स एक बार बेंच दिए हैं। कॉलोनी नगर निगम को अंतरित कर दी। अब वह बबलू के जर्जर होने निवासियों को चेतावनी देने के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही इन संपत्तियों को जबकि उसने नगर निगम को अंशित कर दिया है तो गृह निर्माण मंडल आखिर क्यों खरीद बिक्री पर अंतरण करने की भूमिका निभाता है। यह सब यह सब कार्य फिर पंजीयन विभाग को ही करना चाहिए दूसरी तरफ मंडल का इतिहास रहा है कोई भी योजना कभी भी समय पर पुरी जंबूज करना तो होने दी जाती है और ना पूरी की जाती है जिसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण सांवेर रोड की नई जेल है। जो सन 2002 से बनना शुरू हुई थी। जो 21 साल बाद भी अधूरी है। जबकि पहले जय हनुमान मंडल के उपायुक्तों से लेकर कार्यपालन यंत्रियों ने सैंकड़ों करोड़ बर्बाद कर दिए थे। अपने भ्रष्टाचार नाकामियों को छुपाने उस जेल को बना पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को अंतरित किया गया। उसने भी उसमें सैकड़ो करोड़ बर्बाद करने के बाद में भी वह जेल अभी तक अधूरी है। यही हाल रेनबो रेजीडेंसी में भी हो रहा है। और यही हाल ये 676 एल आई जी के फ्लैट्स तोड़ने बनाने में भी किया जाएगा ताकि अधिकतम पर्यायवाची जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई झोंककर मुश्किल से सिर पर छत की व्यवस्था कर पाए थे और अब जब उनका बुढ़ापा आ गया। तो मकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है क्योंकि अब उन जमीनों की कीमतें हजार गुना तक बढ़ चुकी हैं। कोशिश होगी कि जो 3 साल की बात की जा रही है वह 10 साल में भी मकान पूरे ना हो ताकि अधिकांश रहवासी मर मरा जायें उनके फ्लेटों को आसानी से बैंच के हजम किया जा सके। गृह निर्माण मंडल के इंजीनियर भी बड़े-बड़े समाचार पत्रों के पत्रकारों को महीना बांटते हैं। साथी अधिकांश बड़े समाचार पत्र भास्कर पत्रिका अग्निबाण प्रभात किरण सभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर बड़े भू माफिया कॉलोनी माफिया होने के साथ सैकड़ो करोड़ की संपत्तियों के मालिक हैं। वे भी वहां के रह वासियों की परेशानियों से दूर चाहते हैं। की उनको तोड़कर पुनः बनायें जाएं ताकि उनके महीना खाने वाले पत्रकारों का फायदा होने के साथ भी कुछ फ्लैट्स मकान उनके मालिकों के हिस्से में आएं जिसको बेंच कर मोटी कमाई करेंगे। क्योंकि तिमंजिला तोड़कर सबको आठ मंजिल फ्लैट्स बनाकर बेचने और मोटी कमाई करना है। सरकार बदलते ही मुख्यमंत्री से लेकर नीचे सारे मंत्रियों नेताओं की भी उसकी कमाई में हिस्सेदारी होने के कारण वह भी चाहते हैं जल्दी तोड़फोड़ हो। बेशक हर मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। चाहे वह अधिकारी नेता मंत्री पत्रकार समाचार पत्र का मालिक से लेकर आम आदमी तक चाहता है कि उसके भी नाम पर जमीन जायदाद संपत्ति

फ्लैट्स मकान हों, जिसके लिए वह जीवन भर प्रयास करता रहता है। दूसरी तरफ उन फ्लेटस को पूरा होने बनने तक जैसा कि गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों ने कहा कि वहां के फ्लैट्स धारियों को रु. 12000 प्रति माह दिए जाएंगे। 3 साल में पूरा करने का वादा किया जा रहा है जो 5 से 10 साल तक भी पूरा नहीं हो पाएगा।

गृह निर्माण मंडल के उज्जैन और इंदौर ऑफिस से सूचना के अधिकार में वहां के अधिकारियों वह कार्यों के बारे में सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी जाने परसमय पर जवाब प्राप्त नहीं होते और अपील लगाने पर सामने समय बाधित होने के कारण निशुल्क देने की बात कर दी जाती है। परंतु अपील पर आदेश करने के बाद में उसमें पुनः शुल्क जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार यह हरामखोर उपायुक्त से लेकर नीचे तक सब अपने भ्रष्टाचार की जानकारियां छुपाने के लिए वहां भी छल कपट करते रहते हैं। जिन विभागों का काम इस गृह निर्माण मंडल करने को दिया जाता है यह वहां पर भी जालसाजी करता है जैसा की आईटीआई के बबलू व परिसर की दीवार को तोड़कर आधार से बनाने के निर्माण में नीचे की बनी हुई दीवार पर ही ऊपर कीदो-तीन फुट दीवार बनाकर उसमें ही खंबे लगा तार लगा दिए गए। जबकि भुगतान हरामखोर कर पालन यांत्रियों से उपेंद्र तक पुरी नई निर्माण का लिया गया इसकी शिकायत करने पर आज तक जांच नहीं की जा सकी क्योंकि सभी उसमें हिस्सेदार थे। यही हाल पूरे गृह निर्माण मंडल के सभी कर्मचारियों अधिकारियों का फ्लैट्स के अंतरण कब्जे करवाने अवैध निर्माण करवाने मोटी कमाई खाने खाली पड़ी भूमि पर नेताओं पार्षदों भू माफिया कॉलोनी में माफिया को खुली छूट देने उसमें भी मोटी कमाई करने का षड्यंत्र करते हैं यह हालग्रैनडीएमए मंडल की विकसित और बनाई कॉलोनी फ्लैट्स आदि में न केवल इंदौर के नेहरू नगर एल आई जी से लेकर पूरे इंदौर-धार- झाबुआ- खंडवा- खरगोन के साथ पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है आखिर इन हरामखोरों जालसाजों के मोबाइल टेप क्यों नहीं किए जाते सरकार जनता पत्रकारों के तो फोन टिप करने के साथ निगरानी करती हैजबकि उसे अपने ही अधिकारियों कर्मचारियों की सच्चाई जानने के साथ भ्रष्टाचार और जालसाजियों का आसानी से पता लगा सकती है। शायद इसीलिए नहीं करती क्योंकि भ्रष्टाचारों जालसाजियों को स्वयं संरक्षण देकर कमाई भी तो करती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालय से नीचे सभी मंत्रालयों तक कोई भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत धराचार्य के 25 बिंदुओं की जानकारी को 18 साल गुजर जाने के बाद में भी अभी तक अपलोड नहीं करती। अन्यथा अपने ही बनाए एसओआर या कर की दरों की निर्धारण के बाद भी वर्तमान मूल्य से चार से 10 गुना तक की डीपीआर बना कार्य नियोजन के प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार व लूट का खेल खेला जाने लगता है। और यही कारण है की जनता से 15 सौ से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं पर वसूले गए जीएसटी का लूटा हुआ पैसा निर्माण कार्यों के नाम पर हर कदम हर विभाग में हर तरीके से हजम किया जा रहा है। तो गृह निर्माण मंडलमें बैठे अधिकारी घोर भ्रष्ट जालसाज नेताओं के संरक्षण में यह खेल क्यों नहीं खेलेंगे?

विद्युत कं. के अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए

हर दिन 1 संविदाकर्मी की मौत व स्थाई अपगंता भी

भारत के कारखाना अधि. 1948 में कारखाने की परिभाषा में उत्पादन के साथ सेवा भी शामिल किया जाए। ताकि विद्युत वितरण, सेवा प्रदाता कं. में संविदा ठेका कर्मियों की सुरक्षा की जा सके।

अमेरिकी विश्व घातक आतंकी व्यापार संगठन जिसका उद्देश्य विश्व के देशों की सरकारों को खरीद कर वहां के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों पर षड्यंत्रकारी कानून बनवा कब्जा करना और मोटा लाभ प्राप्त करना था। को 1990-91 में नरसिम्हा राव सरकार ने हस्ताक्षर अवश्य किया परंतु देश में लागू नहीं किया या होने दिया। परंतु बुकेराजन पार्टी की 1999 में सरकार आने के बाद उन्हें अमेरिकी शैतान संघों के षड्यंत्रकारियों ने उन्हें खरीद कर सभी सरकारी मंडलों निगमों कंपनियों में बिना विनिवेशीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय निजी पूंजी पतियों को सौंपने का मोती जली पर षड्यंत्र किया गयाजिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश के सभी राज्यों के विद्युत मंडलों को भी कंपनियों में बदल दिया गया। अरुण कंपनियों के संचालन भारतीय प्रताड़ना सेवा के घोर धूर्त मक्कार जालसाज अधिकारियों को सौंप दिया गया। जिनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से कंपनियों में रहते हुए लूट वसूली करते हुए उनकी आधारभूत अधोसंरचना को कमजोर करते हुए बर्बाद कर घाटे में दिखाकरपूर्ण रूप से पूंजी पत्तियों को मोटी दलाली पर अंतरित करने का षड्यंत्र था। जो पिछले 20 सालों से सतत पूरे देश में यह हरामखोर डकैत भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी सभी शासकीय मंडलों निगमों कंपनियों में कर रहे हैं। सभी कंपनियों में हजारों करोड़ की लूट करने के लिए खरीदी में 20 से 50% तक कमिशन, ट्रांसफार्मर विद्युत लाइनें खंबो विद्युत वितरण केंद्रों उप केंद्रों पर उपभोक्ताओं की लाइन सुधारने, रखरखाव के नाम पर भारी खर्च भर दिखाना, पर ढंग से रख-रखाव ना करना। अप्रशिक्षित शिक्षित कर्मचारियों को आधे अधूरे वेतन पर संविदा व ठेके पर बिना सुरक्षा उपकरणों यथा हेलमेट गम बूट ग्लाव्स का करोड़ों रु का खर्चा दिखा सारा पैसा हजम कर जाना। जानकार शिक्षित इंजीनियर कर्मचारियों की नियमित भर्तीयां न करना, ताकि उन्हें नियमानुसार वेतन व सुविधायें ना देनी पड़े। उन्हें जानवरों की तरह जोत कर काम करने के लिए 12-14 घंटे तक काम लिया जाता है। इसीलिए बिजली के खंबों पर काम करते समय कर्मचारियों के बिना प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरणों के अकाल मौत हो जाने पर उन्हें अपना कर्मचारी मानने से भी मना कर दिया जाता है। जबकि कर्मचारियों चाहे वह ठेका संविदा दैनिक वेतनकर्मी कोई भी क्यों ना हो यदि उसे नियोक्ता के रूप में जिसके अंतर्गत और निर्देश देने वाले उप, सहायक, कार्यपालन अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता कंपनी का प्रमुख प्रबंध संचालक मुख्य महाप्रबंधक सभी ऐसे कर्मचारियों की मौत और अपन्गता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 गैर इरादतन हत्या व मानव बध के दोषी है और उन पर न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वैसे इस संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग जो भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत काम करता है की धारा 2 ट के उत्पादन प्रक्रिया के बिंदु क्रमांक 3 में दर्शाये अनुसार विद्युत के उत्पादन पारेषण और प्रवर्तन में भी संशोधन कर वितरण को भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि सभी सेवा प्रदाता कंपनियां और उन्हें कार्यरत कर्मचारीके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर संबंधित विभाग निरीक्षण कर संज्ञान लेकर जिला एवं सत्र न्यायालयों में धारा 304 की कार्यवाही कर विद्युत कंपनियों में वितरण से संबंधित कर्मचारियों का प्रशिक्षण और उनको सुरक्षा उपकरणों के देने के मामले में व दुर्घटना होने पर पीड़ित पक्षकार को उचित क्षतिपूर्ति दिलवाने में कार्य कर सेवा व वितरण से संबंधित कर्मचारियों के वेतन भत्ते के साथ उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 के अंतर्गत

धारा 304 आईपीसी - IPC 304 in Hindi - सजा और जमानत - हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड

धारा 304 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अनुसार,

जो कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी मे नही आता) करता है अथवा ऐसा कोई कार्य करता है जो मृत्यु का कारण हो, जिसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो, या ऐसी शारीरिक चोट जो संभवतः मृत्यु का कारण हो पहुचाने के लिए किया गया हो, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, या उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा, या ज्ञान पूर्वक ऐसा कोई कार्य करता है जो संभवतः मृत्यु का कारण हो, लेकिन जिसे मृत्यु देने के इरादे, या ऐसी शारीरिक चोट जो संभवतः मृत्यु का कारण हो पहुचाने के लिए से न किया गया हो, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, या उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

लागू अपराध

1. हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या, ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो और जिसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो, आदि।

सजा - आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास + आर्थिक दंड

यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

2. ज्ञान पूर्वक ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो, लेकिन जिसे मृत्यु देने के इरादे से न किया गया हो, आदि।

सजा - 10 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों

यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 304 आई. पी. सी. (हत्या की श्रेणी में न आने वाले गैर इरादतन मानव वध के लिए दण्ड)

आमतौर पर हम सुनते रहते हैं, कि जब किसी व्यक्ति पर कोई हत्या या किसी अन्य व्यक्ति को जान से मारने का आरोप लगाया जाता है, तो ऐसे आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 लगाई जाती है, किन्तु एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने के कई पहलू हो सकते हैं, जैसे उस व्यक्ति का जान से मारने का इरादा न हो या उसने वह हत्या किसी के कहने पर या किसी दवाव में की हो, तो ऐसे मामलों में चूँकि किसी व्यक्ति की हत्या तो हुई ही है, तो जिस व्यक्ति के हाथ से हत्या हुई है, उसे न्यायालय में उसके इस अपराध के लिए उचित दंड देने का प्रावधान है।

इसी कारण वे सभी हत्या के मामले जिनमें मारने वाले व्यक्ति का इरादा नहीं होता है, उन मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 नहीं लगाई जा सकती है, ऐसे सभी मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 लगाए जाने का प्रावधान दिया गया है।

धारा 304 के मामलों में आरोपी को दंड तो दिया जाता है, किन्तु इस धारा में धारा 302 के अपराध से थोड़ा कम दंड देने का प्रावधान दिया गया है। धारा 304 का केस केवल और केवल आरोपी की नियत के आधार पर बनाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर उसे किसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से वार करता है, किन्तु बाद में वह वार उस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाए, तो इस प्रकार के मामले में आरोपी पर धारा 304 के तहत केस चलाया जा सकता है। लेकिन धारा 304 के अपराध के आरोपी को न्यायालय में सिद्ध करना अनिवार्य होगा कि यह हत्या उसने जान बूझ कर नहीं की, बल्कि उस व्यक्ति से धोखे से हो गयी है। यदि आरोपी यह सिद्ध करने में असमर्थ हुआ तो उस आरोपी को धारा 304 की वजाय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दण्डित किया जायेगा।

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 30000 मेगावाट बिजली सरकारी बांधों और कोयल की ताप विद्युत से निमित्त मिलने के साथ सरकार ने लगभग 15 से 20000 मेगावाट बिजली पवन व सौर ऊर्जा के ऊंची कीमतों पर खरीदी के समझौते कई वर्षों पूर्व से कर रखे हैं। परंतु मध्य प्रदेश का एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड अदानी को मात्र जिसकी लगभग कीमत उसके पूरे प्रदेश में पहले लाखों टावर जो 2 लाख करोड रु से ज्यादा थी। मोदी के दवाब के चलते 18000 करोड़ में बेंच कर मध्य प्रदेश की बिजली को चोरी करके पाकिस्तान तक बेचने का षड्यंत्र अदानी कर रहा है परंतु पहले शिवराज और अब मोहन यादव परमुंह बंद रखने का दवाब है। जिसे भास्कर ने लगभग 3 वर्ष पूर्व छपा था कि आखिर 8000 करोड रुपए की बिजली हर माह अडानी पाकिस्तान को कहां से उत्पादित कर कैसे बेंच व भेज रहा है। यह बात सरकार स्वीकार नहीं करती उसकी पर्याप्त लाभ होने के उपरांत भी ये धूर्त भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी जानबूझकर प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को लूटने के बाद में लव होने के उपरांत भी लूट के कारण घाटा दिखाकर बस कर्मचारियों की पर्याप्त भारतीय करने की तो दूर जरूरत के एक तिहाई कर्मचारी ठेके पर बिना प्रशिक्षण दिए रख कर 12 से 14 घंटे काम करवा कर काम चला रही है। इस प्रकार पूरे विद्युत मंडल की उत्पादन से लेकर वितरण तक की बर्बादी कर रही है। जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। आखिर संविदा ठेका दैनिक वेतन भोगी कमी भीइस देश की ही जनता है। कब तक जनता को लूट कर कर्मचारी रूपी जनता का ही शोषण किया जाएगा। पिछले वर्षों में ही प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनियों में बिना पर्याप्त प्रशिक्षण व सुरक्षा उपकरणो के लाइन और खंबों पर काम करने के कारण 500 से ज्यादाठेका संविदा कर्मियों की मौत के साथ 1000 से ज्यादा स्थाई अपन्ग हो गए। पर नियोक्ता कंपनियों ने उन्हें कर्मचारी ही नहीं माना और आम जनता की तरह अकाल मृत्यु पर 4 लाख रु की क्षतिपूर्ति दिलवाने की व्यवस्था करवा दी। वर्तमान में 70000 से ज्यादा ठेका व संविदा कर्मी वितरण कंपनियों में कार्यरत हैं जिनका हर तरह से भरपूर शोषण किया जाता है।

कार्टून कोना

साप्ताहिक समय माया

अदरक

फायदे और रोगों के उपचार

अदरक के फायदे क्या हैं? अदरक एक औषधीय गुणों से भरपूर मसाला है। 100 से ज्यादा बीमारियों में इस चमत्कारी मसाले के औषधीय लाभों पर अनगिनत अध्ययन किए गए हैं।

दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाए जाने वाले मसाले के रूप में अदरक दुनिया का सबसे बहुपयोगी औषधीय गुण वाला पदार्थ है। 100 से ज्यादा बीमारियों में इस चमत्कारी मसाले के औषधीय लाभों पर अनगिनत अध्ययन किए गए हैं। आधे से अधिक पारंपरिक हर्बल औषधियों में इसे शामिल किया जाता है। आइए जानते हैं इसके गुणों को विस्तार से:

अदरक का प्राचीनकाल में प्रयोग

ऐतिहासिक अभिलेखों से भी पहले से भारत और चीन में अदरक को एक मसाले और औषधि के रूप में उपजाया और इस्तेमाल किया जाता था। दोनों देशों के शुरुआती चिकित्सा ग्रंथों में ताजे और सुखाए गए, दोनों रूपों में इस मसाले के औषधीय इस्तेमाल का विस्तार से वर्णन है। चौथी शताब्दी ईसापूर्व के चीनी ग्रंथों में अदरक को पेट की समस्याओं, मतली, दस्त, हैजा, दांतदर्द, रक्तस्राव और गठिया के उपचार के लिए एक औषधि के रूप में बताया गया है। चीन के जड़ी-बूटी विशेषज्ञ इस बूटी का इस्तेमाल सर्दी-खांसी सहित तमाम श्वास संबंधी बीमारियों के उपचार में भी करते हैं। पांचवीं सदी में चीनी नाविक लंबी समुद्री यात्राओं में स्कर्वी के इलाज के लिए अदरक में मौजूद विटामिन सी तत्वों का इस्तेमाल करते थे। भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को सबसे महत्वपूर्ण बूटियों में से एक माना गया है। यहां तक कि उसे अपने आप में औषधियों का पूरा खजाना बताया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सक इसको एक शक्तिशाली पाचक के रूप में लेने की सलाह देते हैं क्योंकि यह पाचक अग्नि को भड़काता है और भूख बढ़ाती है। इसके पोषक तत्व शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। आयुर्वेद में अदरक को जोड़ों के दर्द, मतली और गति के कारण होने वाली परेशानी के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए अदरक के फायदों पर नजर डालते हैं:

1. अदरक कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम

आधुनिक शोधों में अदरक को विभिन्न प्रकार के कैंसर में एक लाभदायक औषधि के रूप में देखा जा रहा है और इसके कुछ आशाजनक नतीजे सामने आए हैं।

मिशिगन यूनिवर्सिटी कांप्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के एक अध्ययन में पाया गया कि अदरक ने न सिर्फ ओवरी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया, बल्कि उन्हें कीमोथैरेपी से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से भी रोका जो कि ओवरी के कैंसर में एक आम समस्या होती है। इस अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने ओवरी कैंसर कोशिकाओं पर अदरक पाउडर और पानी का एक लेप लगाया। हर परीक्षण में पाया गया कि अदरक के मिश्रण के संपर्क में आने पर कैंसर की कोशिकाएं नष्ट हो गईं। हर कोशिका ने या तो आत्महत्या कर ली, जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है या उन्होंने एक-दूसरे पर हमला कर दिया, जिसे ऑटोफेगी कहा जाता है। अदरक को स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर के इलाज में भी बहुत लाभदायक पाया गया है। जर्नल ऑफ बायोमेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित शोध में पता चला कि अदरक के पौधे के रसायनों ने स्वस्थ स्तन कोशिकाओं पर असर डाले बिना स्तन कैंसर की कोशिकाओं के प्रसार को रोक दिया। यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पारंपरिक विधियों में ऐसा नहीं होता। हालांकि बहुत से ट्यूमर कीमोथैरैपी से ठीक हो जाते हैं, मगर स्तन कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है। वे अक्सर बच जाती हैं और उपचार के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती हैं।

अदरक के इस्तेमाल के दूसरे फायदे ये हैं कि उसे कैप्सूल के रूप में दिया जाना आसान है, इसके बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं और यह पारंपरिक दवाओं का सस्ता विकल्प है।

आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि अदरक कोलोन में सूजन को भी कम कर सकता है जिससे कोलोन कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 30 मरीजों के एक समूह को 28 दिनों में दो ग्राम अदरक की जड़ के सप्लीमेंट या प्लेसबो दिए। 28 दिनों के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन मरीजों ने अदरक की जड़ का सेवन किया था, उनमें कोलोन की सूजन के चिह्नों में काफी कमी पाई गई। इससे यह कोलोन कैंसर के रिस्क वाले लोगों में एक कारगर प्राकृतिक बचाव विधि हो सकती है।

कई और तरह के कैंसर, जैसे गुदा कैंसर, लिवर कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, मेलानोमा और पैंक्रियाज के कैंसर को रोकने में अदरक के तत्वों की क्षमता पर भी अध्ययन किए गए हैं। यह एक दिलचस्प बात है कि एक कैंसर रोधी दवा बीटा-एलिमेन अदरक से बनाई जाती है।

2. अदरक मधुमेह में लाभदायक तत्व

मधुमेह के मामले में अध्ययनों ने अदरक को इसके बचाव और उपचार दोनों में असरकारी माना है।

ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध में अदरक को टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए असरदार पाया गया। अदरक के तत्व इंसुलिन के प्रयोग के बिना ग्लूकोज को स्नायु कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। इस तरह इससे उच्च रक्त शर्करा स्तर (हाई सुगर लेवल) को काबू में करने में मदद मिल सकती है।

अध्ययनों में पाया गया है कि अदरक मधुमेह से होने वाली जटिलताओं से बचाव करती है। अदरक मधुमेह पीड़ित के लिवर, किडनी और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सुरक्षित कर सकती है। साथ ही वह इस बीमारी के एक आम दुष्प्रभाव मोतियाबिंद का खतरा भी कम करती है।

3. अदरक हृदय के लिए लाभकारी

अदरक सालों से हृदय रोगों के उपचार में इस्तेमाल होती रही है। चीनी चिकित्सा में कहा जाता है कि अदरक के उपचारात्मक गुण हृदय को मजबूत बनाते हैं। हृदय रोगों से बचाव और उसके उपचार में अक्सर अदरक के तेल का प्रयोग किया जाता था।

आधुनिक अध्ययन दर्शाते हैं कि इस जड़ी-बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, रक्त प्रवाह में सुधार लाने और अवरुद्ध आर्टरियों तथा रक्त के थक्कों से बचाव करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें हृदयाघात और स्ट्रोक के जोखिम को कम करती हैं।

4. अदरक के फायदे पेट के लिए

अदरक को हजारों सालों से प्राचीन सभ्यताओं द्वारा एक पाचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके वात को दूर करने वाले तत्व पेट की गैस को दूर करके पेट फूलने और उदर वायु की समस्या से बचाव करते हैं। साथ ही पेट में मरोड़ को ठीक करने वाले इसके तत्व मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हुए अजीर्णता में राहत पहुंचाते हैं।

भोजन से पहले नमक छिड़क कर अदरक के टुकड़े खाने से लार बढ़ता है, जो पाचन में मदद करता है और पेट की समस्याओं से बचाव करता है। भारी भोजन के बाद अदरक की चाय पीने से भी पेट फूलने और उदर वायु को कम करने में मदद मिलती है। अगर आपको पेट की समस्याएं ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो आप फूड प्वायजनिंग के लक्षणों को दूर करने के लिए भी अदरक का सेवन कर सकते हैं।

स्थायी अपच (डिस्पेप्सिया) के उपचार, बच्चों में पेट दर्द से राहत और बैक्टीरिया जनित दस्त के उपचार में अक्सर अदरक लेने की सलाह दी जाती है।

5. अदरक मोशन सिकनेस को कम करती है

अलग-अलग तरह की मतली और उल्टी को ठीक करने में अदरक बहुत मददगार होती है। गर्भवती स्त्रियों में मॉर्निंग सिकनेस, सफर पर रहने वाले लोगों में मोशन सिकनेस और कीमोथैरेपी के मरीजों में भी मितली की समस्या में यह राहत देती है। कीमोथैरेपी के दौरान वमन रोकने वाली दवाएं दिए जाने के बावजूद 70 फीसदी मरीजों को मितली की परेशानी होती है। वयस्क कैंसर रोगियों पर किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि रोजाना कीमो से पहले आधा से एक ग्राम अदरक की डोज दिए जाने पर अध्ययन में हिस्सा लेने वाले 91 फीसदी मरीजों में तेज मितली की गंभीरता काफी हद तक कम हुई।

अदरक चक्कर आने के साथ आने वाली मितली को भी कम करने में मदद करती है। इस संबंध में हुए शोध से पता चलता है कि इस मसाले के उपचारात्मक रसायन, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में काम करते हुए उबकाई के असर को कम करते हैं।

6. अदरक जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस में राहत देती है

अदरक में जिंजरोल नामक एक बहुत असरदार पदार्थ होता है जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। एक अध्ययन के मुताबिक, अदरक गंभीर और स्थायी इंफ्लामेटरी रोगों के लिए एक असरकारी उपचार है।

कई और वैज्ञानिक अध्ययन भी जोड़ों के दर्द में अदरक के असर की पुष्टि करते हैं। गठिया के शुरुआती चरणों में यह खास तौर पर असरकारी होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित बहुत से मरीजों ने नियमित तौर पर अदरक के सेवन से दर्द कम होने और बेहतर गतिशीलता का अनुभव किया।

हांग कांग में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि अदरक और संतरे के तेल से मालिश करने पर घुटने की समस्याओं वाले मरीजों में थोड़ी देर के लिए होने वाली अकड़न और दर्द में राहत मिलती है।

अदरक कसरत से होने वाले सूजन और मांसपेशियों के दर्द को भी कम कर सकती है। जार्जिया यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लगातार 11 दिन तक 34 और 40 वाटंलियरों के दो समूहों को कच्ची और पकाई हुई अदरक खिलाई। अध्ययन के नतीजों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अदरक के सप्लीमेंट्स का रोजाना इस्तेमाल, कसरत से होने वाले मांसपेशियों के दर्द में 25 फीसदी तक राहत देती है।

7. अदरक माइग्रेन और मासिक धर्म की पीड़ा को कम करती है

शोध से पता चलता है कि अदरक माइग्रेन सिरदर्द में राहत दे सकती है। ईरान में किए गए और फाइटोथैरेपी रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन

में पाया गया कि माइग्रेन के लक्षणों के उपचार में अदरक पाउडर माइग्रेन की आम दवा सुमाट्रिप्टन जितना ही असरदार है।

क्लीनिकल ट्रायल में तीव्र लक्षणों वाले 100 माइग्रेन पीड़ितों में से कुछ को सुमाट्रिप्टन दिया गया और बाकियों को अदरक पाउडर। शोध में पाया गया कि दोनों की प्रभावक्षमता एक जैसी थी और अदरक पाउडर के दुष्प्रभाव सुमाट्रिप्टन के मुकाबले बहुत कम थे। इससे यह पता चलता है कि यह माइग्रेन का अधिक सुरक्षित उपचार है।

माइग्रेन का हमला शुरू होते ही अदरक की चाय पीने से प्रोस्टेग्लैंडिन दब जाते हैं और असहनीय दर्द में राहत मिलती है। इससे माइग्रेन से जुड़ी उबकाई और चक्कर की समस्याएं भी नहीं होतीं।

अदरक डिस्मेनोरिया पीड़ादायक मासिक धर्म से जुड़े दर्द को भी काफी कम करने में मददगार है। ईरान में किए गए एक शोध में 70 महिला विद्यार्थियों को दो समूहों में बांटा गया। एक समूह को अदरक के कैप्सूल और दूसरे को एक प्लेसबो दिया गया। दोनों को उनके मासिक चक्र के पहले तीन दिनों तक ये चीजें दी गईं। शोधकर्ताओं ने पाया कि अदरक के कैप्सूल लेने वाली 82.85 फीसदी महिलाओं ने दर्द के लक्षणों में सुधार बताया जबकि प्लेसबो से सिर्फ 47.05 फीसदी महिलाओं को ही राहत मिली।

बहुत सी संस्कृतियों में जलन के उपचार के लिए त्वचा पर ताजे अदरक का रस भी डालने की परंपरा है और अदरक का तेल जोड़ों तथा पीठ के दर्द में काफी असरकारी पाया गया है।

8. अदरक श्वास की समस्याओं दमा के उपचार में असरकारी

श्वास संबंधी समस्याओं के उपचार में अदरक के तत्वों के सकारात्मक नतीजे दिखे हैं। शोध से पता चलता है कि दमा से पीड़ित मरीजों के उपचार में इसका प्रयोग आशाजनक रहा है। दमा एक स्थायी बीमारी है जिसमें फेफड़ों की ऑक्सीजन वाहिकाओं के स्नायुओं में सूजन आ जाती है और वे विभिन्न पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे दौरे पड़ते हैं।

हाल में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि अदरक दो तरीके से दमा के उपचार में लाभदायक होता है। पहला हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करते हुए और दूसरे हवा के मार्ग को आराम पहुंचाने वाले दूसरे एंजाइम को सक्रिय करते हुए।

अदरक अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी एंटी-इंफ्लामेटरी और दर्दनिवारक तत्वों के कारण असरकारी होती है। इसके गुण नॉन स्टेरायडल एंटी इंफ्लामेटरी दवाओं के समान होते हैं मगर इसके नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं होते। जबकि दमा की बीमारी के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के चिंताजनक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए अदरक जैसे वैकल्पिक, सुरक्षित उपचार का मिलना इस रोग के उपचार में एक आशाजनक खोज है।

9. अदरक और शहद के फायदे - सर्दी-खांसी में लाभदायक

अदरक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है जिससे यह सर्दी-खांसी तथा फ्लू का जाना-माना उपचार है। ऊपरी श्वास मार्ग के संक्रमण में आराम पहुंचाने के कारण यह खांसी, खराब गले और ब्रोंकाइटिस में भी काफी असरकारी होती है।

अदरक सर्दी के समय उत्तेजित होने वाले दुखदायी साइनस सहित शरीर के सूक्ष्म संचरण माध्यमों को भी साफ करती है। सर्दी-खांसी और फ्लू में नींबू तथा शहद के साथ अदरक की चाय पीना बहुत लोकप्रिय नुस्खा है जो पूर्व और पश्चिम दोनों में कई पीढ़ियों से हमें सौंपा जाता रहा है।

अदरक में गर्मी लाने वाले गुण भी होते हैं, इसलिए यह सर्दियों में शरीर को गरम कर सकती है और सबसे अहम बात यह है कि यह सेहत के लिए हितकारी पसीने को बढ़ा सकती है। शरीर को विषमुक्त करने और सर्दी-जुकाम के लक्षणों में लाभदायक इस तरह का पसीना बैक्टीरियल और फंगल संक्रमणों से भी लड़ने में मददगार साबित होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अदरक में सक्रिय पदार्थ होते हैं, जो आसानी से शरीर द्वारा सोख लिए जाते हैं इसलिए आपको उसका फायदा उठाने के लिए उसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती।

10. अदरक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है

दुनिया में हुए बहुत से अध्ययनों में पाया गया है कि अदरक में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लिपिड पेरोक्सिडेशन और डीएनए क्षति को रोकती है।

एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे फ्री रेडिकल्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे उम्र के साथ आने वाली तमाम तरह की बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स और बाकी रोगों से बचाव में मदद मिलती है।

हालांकि सभी मसालों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, अदरक उनमें ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें अपनी 25 अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट विशेषताएं हैं। इसके कारण यह शरीर के अलग-अलग हिस्सों में तमाम तरह के फ्री रेडिकल्स से लड़ने में बहुत असरदार है।

अदरक खाने के फायदे

- ठंड लगने की संभावना कम करता है
- पाचन सुधारता है
- खून साफ करने में मददगार

ध्यान देने योग्य बातें

- दो साल से कम उम्र के बच्चों को अदरक नहीं दी जानी चाहिए।
- आमतौर पर, वयस्कों को एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा अदरक नहीं लेनी चाहिए। इसमें खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाने वाला अदरक शामिल है।
- गर्भवती स्त्रियों को 1 ग्राम रोजाना से अधिक नहीं लेना चाहिए।
- आप अदरक की चाय बनाने के लिए सूखे या ताजे अदरक की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे रोजाना दो से तीन बार पी सकते हैं।
- अत्यधिक सूजन को कम करने के लिए आप रोजाना प्रभावित क्षेत्र पर कुछ बार अदरक के तेल से मालिश कर सकते हैं।
- अदरक के कैप्सूल दूसरे रूपों से बेहतर लाभ देते हैं।
- अदरक खून पतला करने वाली दवाओं सहित बाकी दवाओं के साथ परस्पर प्रभाव कर सकती है।
- किसी विशेष समस्या के लिए अदरक की खुराक की जानकारी और संभावित दुष्प्रभावों के लिए हमेशा डॉक्टर से संपर्क करें।

अदरक और गुड़ की चाय

- चाय की यह स्वास्थ्यकर रेसिपी आपको ताजगी और स्फूर्ति से भर देगी। साथ ही इसमें कैफीन के दुष्प्रभाव नहीं होते।
- एक पतीले में साढ़े चार कप पानी उबालें। पानी के उबलने पर 2 इंच अदरक के टुकड़े को 20-25 तुलसी पत्तों के साथ कूट लें।
- इस पेस्ट को सूखी धनिया के बीजों वैकल्पिक के साथ उबलते पानी में डाल दें।
- 2-3 मिनट तक उबलने दें।
- चाय को कप में छान लें और स्वाद के लिए 1 चम्मच नीबू का रस और गुड़ मिलाएं। गरम-गरम पिएं।

साप्ताहिक समय माया

क्या जुलाई के बाद नई सरकार बनेगी?

पेज 1 का शेष

इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार बजट भी मात्र 4 महीने अर्थात अप्रैल मई जून जुलाई तक कहीं प्रस्तुत किया गया इससे संदेह उत्पन्न होता है कि शायद जुलाई के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव को हटाकर नई सरकार का गठन किया जाएगा या मोदी की जीत के बाद पूरे देश के राज्यों की सत्ताओं को खत्म कर देंगे और सारा खेल दिल्ली से चलाया जाएगा। जैसा कि समय माया ने प्रकाशित किया था की तीनों राज्यों में कठपुतली मुख्यमंत्री बैठा दिए गए। और यह तीनों कठपुतली मुख्यमंत्री जैसा मोदी उसके पूंजीपति मित्र और धूर्त पूंजीपतियों के गुलाम कमीशन खोर भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी इन तीनों राज्यों के अधिकारियों को निर्देशित करते हैं वह वैसा ही सरकार को सलाह देकर कार्य करते हैं ताकि पूंजीपति मित्रों और गुजराती ठेकेदारों को बड़ा फायदा पहुंचाया जा सके इसीलिएन केवल राज्यों का बल्कि केंद्र सरकार का भी जनता से 1500 से ज्यादा वस्तु में लूट गया जीएसटी का अधिकांश पैसा अधोसंरचना यथा सड़कें, रेलवे लाइन, बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर सो स्मार्ट सिटी बड़े-बड़े बांध जो केंद्र सरकार के कार्य व सामग्री की निर्धारित दरों से 4 से 10 गुना ज्यादा है।

2024-25 के बजट अनुमान में आय व खर्च

- कुल राजस्व प्राप्तियां रु. 2,52,268.03 करोड़
- राज्य कर से राजस्व प्राप्तियाँ रु. 96,553.30 करोड़
- गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ रु. 18,077.33 करोड़
- राजस्व व्यय रु. 2,51,825.13 करोड़
- पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय रु. 2,31, 112.34 करोड़
- बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य रु. 442.90 करोड़
- कुल पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान रु. 59,718.64 करोड़
- कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान रु. 59,342.48 करोड़

मोदी की गारंटी पर काम- जगदीश देवड़ा

इससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार सुबह पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मप्र सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। अभी चार माह के लिए अंतरिम बजट ला रहे हैं, लिहाजा कोई नई योजना फिलहाल नहीं लाई जा रही है। अंतरिम बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार आम चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी।

कांग्रेस विरोध में उतरी

विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर कुछ बदलाव दिखे, तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही है। विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि जब 2023-24 का 58% बजट ही खर्च हुआ है, 42 प्रतिशत बजट बकाया है तो मप्र के ऊपर नया कर्जा क्यों लादना चाह रही है? हम इस लेखानुदान का समर्थन नहीं कर सकते।

कांग्रेस नेताओं को नोटिस पर बिफरे सिंघार

कांग्रेस नेताओं को आयकर विभाग के नोटिस को लेकर उमंग सिंघार ने कहा कि पांच साल पहले के जवाब आज क्यों मांगे जा रहे हैं। चुनाव आ गए हैं, तो दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। पांच साल में जवाब क्यों नहीं मांगे। यह सीधे-सीधे आइटी विभाग के माध्यम से भाजपा सरकार की कांग्रेस के नेताओं को ब्लैकमेल करने की राजनीति है।

ये होंगे प्रविधान

मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रविधान किया जाएगा। लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली एक हजार 250 रुपये की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा तो किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। तीन वर्षों के लिए 105 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है। प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए सात एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लेखानुदान में अंशदान रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री जन-मन और आवास योजना पर भी रहेगा जोर

लेखानुदान में विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) बहुल क्षेत्रों में आवास निर्माण, सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सहित अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत राज्यांश रखा जाएगा। तीन वर्ष में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये इस योजना में व्यय होंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए भी राज्यांश की व्यवस्था की जाएगी।

इन मदों के लिए भी होगा आवंटन

इसके अलावा अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए राशि निर्धारित की जाएगी। आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना, जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या में वृद्धि, सिंहस्थ 2028, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को राशि आवंटित की जाएगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार ने अंतरिम बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस अनुपात में प्रदेश सरकार राज्यांश की व्यवस्था करेगी। एकीकृत पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए भी प्रतीकात्मक प्रविधान किया जा सकता है।

केवल मोटे कमीशन के लिए जनता से लूट हुआ पैसा खर्च करके बनवाई जा रहे हैं चैन को सदुपयोग हो या ना हो जैसा कि आपने देखा देवास में 55 करोड़ से दो किमी लंबा पुल बना दिया गया। इंदौर में भी 10 साल पहले बना कलेक्टर और निगमायुक्त की मनमानी और लूट के लिए बीआरटीएस में 11.5 सौ करोड रु से ज्यादा जेएनआरयुएम व अन्य मदों से खर्च करने के बाद में भी लगातार सड़कें खोदी जाती रहती हैं। जनता से अपनी लूट व कमीशन खोरी को पूरा करने के लिए उस पर नए-नए बहानों से कर थोपे जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परिवहन विभाग के शुल्क 10 गुना तक ज्यादा लिये जा रहे हैं। मोदी जनता उसके भ्रष्टाचार, कुकर्मों, लूट, खसोंट डकैती, नाकामियों बढ़ते अपराधों के बारे में बातचीत ना करेंया करें तो उसकी निगाह में रहे यही कांड अपने केंद्र व राज्यों के सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों निरीक्षकों के मोबाइल टेप व रिकार्डिंग करके क्यों नहीं पता लगाती कि उसके सरकारी कर्मचारी अधिकारी किस तरह से लूट खसोंट भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो जनता के अंटशंट लूटे हुए करों के पैसे से अपने ही सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को समय पर वेतन, छात्रों को छात्रवृत्ति, ठेकेदारों आपूर्ति कर्ताओं को भुगतान देने में असक्षम है। वैसे भी प्रदेश की सरकार के कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को बताया अवश्य गया है परंतु सारा खेल अपने मित्रों के फायदे के लिए दिल्ली से चलाया जा रहा है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया लेखानुदान, करारोपण संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए जाने वाले लेखानुदान के माध्यम से विभिन्न विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की गई है।

1. मोहन सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी।
2. एक लाख 45 हजार करोड रुपये का लेखानुदान पेश किया गया है।
3. लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के नए मद सम्मिलित नहीं हैं।

दूसरी तरफ कांग्रेस को बदनाम करने वाले इन हरामखोर जालसाजों को केवल लूट से मतलब है। इसलिए 2014 में मोदी की सत्ता संभालने के बाद अपनी लूट भ्रष्टाचार को छुपाने और करने के लिए हर तरह से हर कदम षड्यंत्र किया जा रहे हैं यहां तक की भारत के केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सांख्यिकीय विभाग जो हर तरह के आंकड़ों व समंको का संकलन करता था। वहां भी अपनी बहादुरी झूठी सफलता की कहानी और उपलब्धियां दिखाने के लिए सारे फर्जी आंकड़ों का खेल किया जा रहा है। जिसके आधार पर हर क्षेत्र में नीति निर्धारण कर जनता से वसूला धन खर्च किया जाता था। उन्होंने अपने भ्रष्टाचार जालसाजियां और लूट करने नीचे स्तर से ही आंकड़ों के संकलन व प्रस्तुति में भी फर्जी वाड़ा शुरु कर अंतिम बिंदु भारत के सांख्यिकी विभाग को देना शुरू कर दिया। अब जब उसके आधार पर सारा खेल होगा तो समझ सकते हैं। कि बजट की प्रस्तुति कैसे की जाएगी? वैसे भी बजट सरकार में बैठे भारतीय प्रताणना सेवा के अधिकारियों के साथ सत्ताधीश दल की अपनी मोटी कमाई और सत्ता में बने रहने के शैलेंद्र का हिस्सा होती है और इस बार के बजट में भी यही किया गया। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए करारोपण नहीं किया गया। लाडली बहना के लिए अगले 4 महीना के भुगतान के लिए 6.5 हजार करोड रुपए की व्यवस्था कर दी गई।

1.45 लाख करोड़ रुपये का लेखानुदान विधानसभा में पेश

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा लेखानुदान पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 206 (1) के अंतर्गत अत्यावश्यक निरंतर व्यय के मदों के लिए नई सेवाएं या व्यय के नए मद/ शीर्ष सम्मिलित नहीं हैं। लेखानुदान का उद्देश्य 'अंतिम आपूर्ति' की स्वीकृति होने तक सरकार के क्रियाकलाप को जारी रखना है। करारोपण संबंधी नए

मप्र विधानसभा के चालू सत्र में सोमवार को मोहन सरकार द्वारा लेखानुदान पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। मोहन सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की गई है। कुल एक लाख 45 हजार करोड रुपये का लेखानुदान पेश किया गया है। लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के नए मद सम्मिलित नहीं हैं। इसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शामिल नई योजनाओं के लिए प्रविधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि चार माह बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में शामिल की जाएगी।

इस लेखानुदान में औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने, सड़क नेटवर्क मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने के लिए भी धनराशि का प्रविधान किया गया है।

सम्मिलित नहीं किए गए हैं। द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित नवीन योजनायें के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह लेखानुदान चार माह (1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024) हेतु लागू रहेगा। इसकी की पुनरीक्षित मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। लेखानुदान से प्राप्त राशि मुख्य बजट में समाहित की जाएगी। 1.45 लाख करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया गया है।

बजट अनुमान 2024-25 का वार्षिक वित्तीय विवरण

वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियां राशि 2,52,268.03 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां 96,553.30 करोड़ रुपये है। गैर-कर राजस्व प्राप्तियां 18,077.33 करोड़ रुपये है। बजट अनुमान में राजस्व व्यय 2,51,825.13 करोड़ रुपये है। वर्ष 2023-24 में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय 2,31,112.34 करोड़ रुपये है। वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य 442.90 करोड़ रुपये है। कुल पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान 59,718.64 करोड़ रुपये है एवं वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़ रुपये है।

कांग्रेस करेगी लेखानुदान का विरोध

विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि 2023-24 का 42% बजट ही खर्च हुआ है। ऐसे में अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है? हम लेखानुदान का विरोध करेंगे। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर दिखे, तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही है।

मप्र में चार महीने के लिए अंतरिम बजट पेश, कोई नई योजना या टैक्स नहीं

मध्य प्रदेश विधानसभा में डॉ. मोहन यादव सरकार सोमवार को लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। एक लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश होगा। अंतरिम बजट होने से नई घोषणा या योजना की संभावना कम ही है। सरकार की मौजूदा योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सदन में लेखानुदान पेश करेंगे। इसकी जानकारी सभी सदस्यों को पैन ड्राइव के माध्यम से दी जाएगी। लेखानुदान में प्रधानमंत्री जन मन योजना के लिए बजट घोषित होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विकास कार्यों और बैगा, भारिया, सहरिया परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर आवास स्वीकृत होंगे। इसमें दो लाख रुपये किश्तों में दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही राजस्थान के साथ शुरू होने वाली पार्वती कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए भी राशि का आवंटन किया जा सकता है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत तो राज्यों को 10 प्रतिशत अंश देना है। कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते, पारिश्रमिक में वृद्धि, अधोसरंचना और सिंचाई से जुड़ी विकास परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया जा सकता है।

रू. 988 करोड़ में इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन होगा

सिंहस्थ 2028 की आड़ में लूट का तांडव

लोक निर्माण विभाग में ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट प्रभारियों का प्रभार से बोलबाला

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग अपने भ्रष्टाचारों के लिए प्रारंभ से ही कुख्यात रहा है और भाजपा के आने के बाद इन भ्रष्टाचारों में हर कदम हर प्रकार के भ्रष्टाचार में नई भर्तियां ना कर भ्रष्टों और जालसाजों से मोटा प्रभार ले प्रभार दे चार चांद लगा दिए। सीपीडब्ल्यूडी पूरे देश में निर्माण कार्य संबंधी मंत्रालयों में कार्यों व सामग्री की बाजार मूल्य और आवश्यकताओं के अनुसार दरें निर्धारित कर अपना एस ओ आर जारी करता है। जो पूरे देश के सभी राज्यों के निर्माण कार्यों पर एक समान लागू होता है। उसमें भी 10 से 20% तक का ठेकेदारों की कमाई के साथ अधिकारियों मंत्रियों की कमाई की भी व्यवस्था रखती है। उन दरों से भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 10 से 20 गुना ज्यादा की डीपीआर बना बनवा 50 से 80% तक कमीशन खाने बैंकों से ऋण स्वीकृत करवा काम करने का बैंकों में जमा जनता के धन को हजम करने और बाद में उसे माफ करने का षड़यंत्र तो भाजपा के आने के साथ शुरू हो ही गया था। फिर उसके बाद उसे 10 गुना की ज्यादा डीपीआर का फिर धन सड़कों पर भारी भरकम टोल टैक्स लगा वसूल ने का षड्यंत्र नितिन गडकरी कर ही रहा है।

अब वही षड़यंत्र राज्यों के लोक निर्माण विभाग में भी चलने लगा है यही कारण है की इंदौर से उज्जैन तक की, सिंहस्थ 2028 की तैयारी में 48 किलोमीटर सड़क भी 988 करोड़ में बनाई जाएगी। जबकि इसकी आधी लागत में ही दो नई फोर लेन सड़कें अलग से बनाई जा सकती है।

ताकि यातायात का दबाव एक ही सड़क पर न होकर अलग-अलग होने के साथ उससे लगे हुए गांवों को भी अच्छी सड़कों की सुविधायें मिल सकें। दूसरी तरफ पिछले सिंहस्थ 2016 में लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, शहरीय विकास, स्वास्थ्य जनसंपर्क आदि विभागों में हुए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच और पूछताछ की अपेक्षा उल्टे ही भ्रष्ट अधिकारियों इंजीनियरों को पुरस्कृत किया गया। और पुनः सिहस्थ 28 के नाम 4 वर्ष पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी गई। बेशक पूरे लोकमान्य विभाग में इंजीनियर अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता व स्वीकृति से स्टाफ 25% ही बचा है जिसके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की षड्यंत्रकारी नीति एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन के नाम पर पदोन्नतियां ना देना और दूसरी तरफ उच्च पदों के प्रभार के नाम पर मोटा प्रभार व मासिक वसूली का खेल अनवरत पद पर बैठने से लेकर चला रहा और अपने मुख्यमंत्री को भी आखिर मोदी की चरण दासी में धन भेंट करना होता है। वह भी भर्तीयां व स्थाइ पदोन्नतियां करने की अपेक्षा प्रभातर का खेल सतत चलाये रखना चाहता है।

वैसे हाल ही में विधानसभा चुनाव में सभी संभागों की कार्यपाली नियंत्रण में मतदान केंद्रों की चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं के नाम पर भारी भ्रष्टाचार से मोटी कमाई की है और पुनः लोकसभा चुनाव सामने है उसमें पुनः मतदान के दो पर रैंप बनवाने पानी, छाया, मतदान दल के लिए सोने खाने रहने की व्यवस्था करने कैमरे लाइटिंग पंखे लगवाने के नाम जिलाधीशों के साथ मिलकर 50 से 80% पैसा हजम कर लिया जाएगा क्योंकि स्थाई व्यवस्थाएं तो हाल ही के विधानसभा चुनाव में हर मतदान केंद्र पर की गई थी उन्हीं को नया बता फर्जी बिलों के माध्यम सेपैसा हजम कर लिया जाएगायही कारण है कि यह मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री कर पालन यंत्री सूचना के अधिकार में जानकारी देने और अपील लगाने पर उसको डालते रहते हैं इंदौर में भी प्रभारी मुख्य अभियंता खरात, अधीक्षण यंत्री रावत और यहां बैठे सारी कार्यपालन यंत्री यथा संवाद क्रमांक एक मनोज सक्सेना दो में सोनी, सेतू में दीपेश गुप्ता जिसने 17 साल की उम्र में ही इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर लोक निर्माण विभाग की नौकरी में आ गया था। भारी हरामखोर भ्रष्ट होने के साथ सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जानकारी देने की अपेक्षा भारी भरकम हजारों रुपए में फोटोकॉपी शुल्क मांगा जाता है। अफीम की सुनवाई भोपाल में होती है और वहां बैठे उनके आका क्योंकि महीना खाते हैं इसलिए इन हरामखोरों के

विरुद्ध कोई निर्णय नहीं देते। पिछले 5 साल से ज्यादा समय से बैठा इ एंड एम का प्रभारी कार्यपालन यंत्री डिप्लोमा धारी बीके जैन जिसके पास आठ जिले हैं। शीघ्र स्थानांतरित किया जाना चाहिए डफर केवल लूडो और लूडो के डंपर बैठा हुआ है और विद्युत सामग्री के बिलों में विभागीय सूत्रों के अनुसार भारतीय उत्पादकों को लगाए जाते हैं। परंतु सस्ता चीनी माल जिसमें बल्ब ट्यूबलाइट पंख से लेकर वायरिंग तक बहुत ही निम्न स्तर की होती है। इससे पूरा स्टाफ इसके अंतर्गत सहायक यंत्री और उपयंत्री हैं। सब इसकी मूढ़ता से परेशान है। पर यह बंदा भी समय पर ईएमआई पहुंचाने के करण कुंडली मारे बैठा है आखिर चुनाव आयोग कब कार्रवाई करेगा। यही हाल संभाग एक दो सेतु भवन राष्ट्रीय राजमार्ग इ एंड एम अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता कार्यालय में भी पूरे प्रदेश में बैठे सहायक यांत्रियों उप यांत्रियों का भी है। जो बरसों से इंदौर उज्जैन व पूरे प्रदेश में कुंडली मारे बैठे हैं आखिर जिलों से कब बाहर भेजे जाएंगे। जो चुनाव में स्थानीय नेताओं को हर तरह का यह था उनके क्षेत्रों के काम के साथ वोटिंग से गिनती तक भरपूर सहयोग दे चावन को प्रभावित करते हैं। आखिर कब बदले जाएंगे? साथ ही भवन संभाग में उप यंत्री अजय यादव जो प्रभारी सहायक यंत्री है को भी प्रभार में भी कार्यपालन यंत्री का एक प्रभार और दे दिया गया। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नियम विरुद्ध जातिभाई होने के कारण उसको कार्यपालन यंत्री का प्रभार दिलवा दिया। वैसे भवन निर्माण में भी चारों तरफ भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसमें मूल निर्माण के नक्शे को बदलने से लेकर फाउंडेशन डालने स्तरहीन कम कीमत की सामग्री उपयोग करने से लेकर खिड़की दरवाजे पंखों लाइटिंग आदमी भ्रष्टाचार करने की परंपराओं के साथ समय विस्तार, महंगाई आदि में भी यहां बैठा प्रभारी मुख्य नेता जिसके पास 12 जिलों का प्रभाव है मोटी वसूली कर रहा है। यही कारण है सूचना के अधिकार काम में जानकारी न देने पर अपील लगानेके बादअपीलों के निर्णय नहीं दिए जाते नहीं धारा 4 में सारी जानकारी साइटों पर अपलोड की जाती है।

बेशक यही हाल न केवल इंदौर-उज्जैन कमिश्नरी का ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का है। गर्मी का मौसम शुरू होने जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है सभी भवन एवं पथ के कार्यपालन यंत्री से उपयंत्रियो तक सड़कों के सुधार कार्य के लिए डामर की खरीद और वाले वाले बिक्री का खेल भी होगा। और विभागीय मजदूरों से काम करवा कर फर्जी बिलों से भुगतान ले लिया जाएगा। फिर विभागीय मंत्री राकेश सिंह को भीसभी को महीना पहुंचना पड़ता है। स्पष्ट हैकि यह सब भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार के लिए बने हैं।

विश्व का सबसे बड़ा शैतान अमेरिका युद्धों में क्यों डाल रहा घी...

पेज 1 का शेष

यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है,जनता के चुने हुए शासन के नाम पर बड़े पूंजीपति उत्पादक अपने मनमर्जी के उम्मीदवारों को मोटा चुनावी चंदा व धन देकर सरकार बनवा अपने मोटे फायदे के लिए विधि व हर क्षेत्र की नीति निर्धारण करना कानून बनवाना करो से वसूली करना सरकारों को जनता का शोषण करने अपने तरीके से हांकती हैं। वही हाल अमेरिका में भी है। हथियार उत्पादक कंपनियां अमेरिकी सरकारों को विश्व में जहां उनका बस व्यापार और लाभ नहीं होता उन देशों को अपनी चंगुल में फंसदे उनको परेशान करने उनके विरुद्ध षड़यंत्र रच कर युद्ध करवा युद्ध में कमजोर करने फिर सहायता के बहाने उस देश में घुसने वहां के प्राकृतिक मानव संसाधनों को कब्जे में लेकर अपना मोटा लाभ देखते हैं यही सब कुछ रूस के साथ अमेरिकी कंपनियां करने के लिए रूस के ही हिस्सा रहे देशों के साथ अमेरिका और उसकी षड़यंत्रकारी कंपनियां उनको छल बल दल धन देकर और उसके खिलाफ खड़ा करती रही है। बेशक 1970 से अमेरिका वहां की सरकार है और हथियार उत्पादक कंपनियां सोवियत संघ को तोड़ने के लिए हर तरह के लगातार षड्यंत्र करते रहा। और मिखाइल गोर्बाचोव के आने के बाद आसानी से होंगे उसको खरीद कर सोवियत संघ के 1991 तक 26 टुकड़े कर दिये। उसकी खान-खंड बिखरने के बाद अमेरिका ने उसके अलग हुए देश को खरीदना धन छल बल की सहायता कर रूस को गिरने के लिए उन देशों को नाटो में शामिल करने का ना होना तो मुझे शामिल करने का षड़यंत्र निरंतर जारी रखा। उसमें पहले चेचेन्या और उसके बाद में क्रीमिया अब यूक्रेन जिसमें 2019 मैं अमेरिकी समर्थित जेलेंस्की के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने उसको आर्थिक सहायता देने के साथ रूस को घेरने नाटो में शामिल करने के लिए उकसाया जो कि रूस के हितों के खिलाफ व उसको

सामरिक रूप से कमजोर करने का हिस्सा था। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को समझने की कोशिश की। नहीं मानने पर आखिर 24 फरवरी 2022 को आक्रमण करना पड़ा। कब से अभी तक अमेरिका और उसके नाटो देश यूक्रेन को लगातार आर्थिक और सामरिक सामग्री उपलब्ध करवा यूक्रेन को नष्ट करवाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं ताकि सहायता के बहाने पुनः अमेरिका रूस के पड़ोसी यूक्रेन में घुसकर वहां की गैस व अन्य कीमती खनिजों पर कब्जा कर सकें।

शैतान अमेरिका और उसकी हथियार उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया में युद्ध इसलिए भी करवाती है। ताकि उनके हथियारों की मारक क्षमता का प्रदर्शन विश्व को दिखाने के साथ उनकी मारक क्षमता देख विक्रय को प्रोत्साहन मिल सके। उनके लिए हिंसा मार काट नरसंहार बर्बादी उनकी हथियारों की बिक्री का हिस्सा है। इसलिए उन्हें किसी की बर्बादी तबाही से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को खाने और उठाने के लिए वर्तमान में केवल चीन सक्षम है। पर चीन भी दुनिया के देशों में कब्जा करने के लिए अपने सस्ते माल की बिक्री के साथ वहां के उत्पादन श्रृंखला को छिन्न भिन्न कर देता है। फिर कमाई के मामले में चीन और अमेरिका विश्व के सामने भले ही एक दूसरे के दुश्मन दिखते हों। परंतु षड्यंत्र दोनों के एक जैसे ही हैं। जैसा की विश्व की जनता ने भी कोरोना में देखा। कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनके विक्रय प्रबंधक विश्व घातक संगठन WHO ने फर्जी बीमारी की आड़ में पूरी दुनिया में लाखों करोड़ की दवाइयां ऑक्सीजन प्लांट एक्स-रे मशीनों से लेकर मास्क सैनिटाइजर ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर सैकड़ो गुना कीमत पर बेंच कर मोटी कमाई की। फिर चीन के बने हुए मोबाइल में सारे सॉफ्टवेयर गूगल के माध्यम से डाउनलोड किए जाने के साथ सारे सॉफ्टवेयर गूगल के ही होते हैं जो सिद्ध करते हैं की कमाई के मामले में चीन और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन नहीं सगे दोस्त हैं। और इस श्रृंखला में यदि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो का सहयोग है तो रूस में भी चीन के बने हुए हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि चीन रूस की युध्द की कमजोरी का फायदा उठा उसके गैस पेट्रोल और सामरिक हथियारों की कॉपी कर हजारों के मामले में भी अमेरिका के बराबरी में खड़ा हो सके।इसलिए वे दोनों कुछ मामलों में एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। बेशक ताइवान और दक्षिणी कोरिया के मामले में वे एक दूसरे के सामने आए। एक दूसरे को खुले में धमकियां दीं। पर इन सबसे दूर एक दूसरे के व्यापारिक हितों को कमाई के मामले में आपसी सहयोग बना रहा। क्योंकि चीन भी अब हथियार उत्पादक देश बन गया है इसलिए वह भी अमेरिका की राह पर चलकर अपने हथियारों का प्रदर्शन करने के लिए विश्व में युद्ध होते और करवाते रहना चाहता है। यही कारण है की न केवल रूस और यूक्रेन वरन हमास गाजा का इजराइल से युद्ध लंबा खींचना जा रहा है इन दोनों में ही अमेरिका की शैतानियत की ही भूमिका है।

साप्ताहिक समय माया

आत्यधिक घातक

आसानी से तबाही में उपयोग

मित्र का व्यवसाय बढ़ाने, मौत को दावत

प्रारंभ से ही आक्रमण में उपयोग, लाभ की अपेक्षा सबकी सुरक्षा का खतरा ज्यादा

ड्रोन का आविष्कार तो विश्व में वैमानिकी के विकास के साथ ही 1910 से एरो मॉडल या लघु खिलौने के रूप में शुरू हो गया था। वायु पर तैरने के लिए पक्षियों की भांति रबर और सूक्ष्म इंजन से पंखे घूमा उड़ान भरने व वायु पर तैलने योग्य ढांचे की व्यवस्था की जाती थी। और सभी बड़े विमानों के पूर्व में उनके छोटे एरो माडल बनाकर उनका परीक्षण किया जाता था। जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग युद्ध के मैदानों में चौकसी जासूसी और छोटे-मोटे हमले करने के लिए प्रयोग में ले जाते थे जिसे स्वयं सेनानी स्वीकार किया कि सबसे गंदे असुरक्षित हथियार हैं। मोदी का अडानी प्रेम जग जाहिर है। अदानी ने एक विदेशी ड्रोन कम बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण कर लिया उसके बाद से मोदी ड्रोन की बिक्री प्रवर्तक व प्रबंधक रूप में कार्य करते हुए सार्वजनिक मंचों से उसके खेती मेंदवा पहुंचने में अपराधों पर जनता के दंगे फसाद आंदोलन प्रदर्शनों पर निगरानी करने के लिए शासकीय विभाग में मशीन को कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए कहने बताने और समझने लगे। हाल ही में किसानों के आंदोलन पर भी ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले बरसाए गए। जबकि व्हाट्सएप पर ही एक खबर यह भी प्राप्त हुई की पुलिस ने किसी भी आसुं गैस के गोले को ड्रोन से नहीं टपकाया यह सारा खेल उसकी पितृ संस्था आरएसएस का था। जिसका पता किसानों ने ड्रोन को उलझने और रोकने पतंग उड़ा धागों में फंसा कर टपकाया तब मालूम पड़ा।

दूसरी तरफ ड्रोन या मानवहीन तरंग नियंत्रित उड़ान वाहन की बिक्री के संबंध में भले ही मूढ़ मोदी उसके विक्रय प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हो पर उसका उपयोग से ज्यादा सब की सुरक्षा के लिए घातक दुरुपयोग ज्यादा है। जब अपराधी आतंकवादी आसानी से इन विभिन्न प्रकार के ड्रोन का उपयोग कर थानों, कारागृहों सरकारी कार्यालयों शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालय मानव बस्तियों फैक्ट्री तेल डिपो गैस डिपो, नेताओं सभाओं भंडारण केंद्रों आदि पर इसका दुरुपयोग करेंगे तब सरकारों को समझ में आएगा। बेशक राजनीतिक दल इनका दुरुपयोग जनता में भय फैलाने, तबाही मचाने और फिर एक दूसरे पर दोषारोपण करने मैं करने के साथ एक दूसरे के नेताओं की हत्या करने में भी खुलकर प्रयोग करेंगे। तब राज्यों की पुलिस के पास इनकी जांच नियंत्रित करने दोषियों कोसजा दिलवाने में नाकाम रहेगी।

पिंकी विक्रय प्रबंधन से ज्यादा जरूरी था कि सरकार इन से संबंधित अपराध की संभावना या होने पर इनको रोकने नियंत्रित करने पकड़ने उतारने धूम को उड़ाने में की जा रही रेडियो तरंगों की लंबाई संकेत को पकड़ने दिशा मोड़ने, उसमें रखी वस्तुके बारे में जानने की तकनीकी व्यवस्था उपकरण प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था अपने थानों में कर लेती और यदि इसके लिए सरकार ने ड्रोन संबंधी अपराधों को थानों में जांच नियंत्रण स्रोत आदि की व्यवस्था करने मैं मैं हजारों करोड़ का खर्च आने के साथ-साथ थानों के भवनों में भी रडार, ड्रोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जा रहे रेडियो तरंगों को जानने स्रोत को पकड़ने की व्यवस्था के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होगी। अन्यथा सरकारों के नेता मंत्री अधिकारियो के साथ जनता व उसके जानमाल की सुरक्षा के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध होगा। मित्र के लिए जनता और देश के संसाधनों की बलि चढ़ाई जाना कहां तक उचित होगा?

इसके बारे में एक बात और स्पष्ट कर दूंशासन कितनी भी अच्छी नीति बना लेड्रोन का आपराधीके विध्वंसकारी उपयोग प्रारंभ से लेकर उसके अंत तक होता रहा है और रहेगा। बेहतर होगा सरकार और उसका प्रधान मंत्री मूढ मोदी इसके व्यावसायिक प्रवर्तन से बेहतर होगा कि उसको चंद्रपुर राज्य के शासकीय स्तर परथानों में हवाई अड्डे की तरह रडार रेडियो तरंगों को पकड़ने स्रोत जानने उसको उतारने गिरने रोकने की व्यवस्था के लिए हर थाने में हेलीपैड, हेलीकॉप्टर को उड़ाने रखरखाव करने की व्यवस्था भी करे। ताकि अपराधियों आतंकियों द्वारा व्यापक विध्वंस व तबाही नहीं की जा सके। ऐसी ही व्यवस्था हर नेता अधिकारी पूंजीपति के सार्वजनिक कार्यक्रमों के आसपास भी पुलिस को ही करनी पड़ेगी इसके लिए ना तो सरकार के पास पैसा है और ना पुलिस के पास साधन और प्रशिक्षित स्टाफ तू काहे को स्वयं भोजन ताकि मौत को दावत दी जा रही है।

इसके बारे में विकिपीडिया, नि:शुल्क विश्वकोष से...

मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), जिसे आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है, एक विमान है जिसमें कोई मानव पायलट, चालक दल या यात्री नहीं होते हैं। यूएवी मूल रूप से बीसवीं सदी में सैन्य अभियानों के लिए विकसित किए गए थे, जो मनुष्यों के लिए भी 'सुस्त, गंदे या खतरनाक' थेड

और इक्कीसवीं सदी तक, वे अधिकांश सेनाओं के लिए आवश्यक संपत्ति बन गए थे। जैसे-जैसे नियंत्रण प्रौद्योगिकियों में सुधार हुआ और लागत कम हुई, उनका उपयोग कई गैर-सैन्य अनुप्रयोगों में विस्तारित हुआ।

इनमें हवाई फोटोग्राफी, सटीक कृषि, जंगल की आग की निगरानी,
नदी की निगरानी,
पर्यावरण की निगरानी,
पुलिसिंग और निगरानी, बुनियादी ढांचे का निरीक्षण, तस्करी, शामिल हैं।

उत्पाद वितरण, मनोरंजन और ड्रोन रेसिंग।

बिना किसी व्यक्ति के उड़ान भरने वाले विमानों के लिए कई शब्दों का उपयोग किया जाता है।

ड्रोन शब्द का उपयोग विमानन के शुरुआती दिनों से ही किया जाता रहा है, कुछ का उपयोग दूर से उड़ाए जाने वाले लक्ष्य विमानों पर किया जाता है, जिनका उपयोग युद्धपोत की बंदूकों की फायरिंग

का अभ्यास करने के लिए किया जाता है, जैसे कि 1920 के दशक की फेयरी क्वीन और 1930 के दशक की डी हैविलैंड क्वीन बी। बाद के उदाहरणों में जीएएफ जिंदिविक द्वारा अंतिम प्रतिस्थापन से पहले एयरस्पीड क्वीन वास्प और माइल्स क्वीन मार्टिनेट शामिल थे। यह शब्द आम उपयोग में बना हुआ है। सॉफ़्टवेयर के अलावा, स्वायत्त ड्रोन कई उन्नत तकनीकों का भी उपयोग करते हैं जो उन्हें मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने मिशन को पूरा करने की अनुमति देते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विज़न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और थर्मल सेंसर।

मनोरंजक उपयोग के लिए, हवाई फोटोग्राफी ड्रोन एक ऐसा विमान है जिसमें प्रथम-व्यक्ति वीडियो, स्वायत्त क्षमताएं या दोनों हैं।

एक मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) को 'संचालित, हवाई वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक मानव ऑपरेटर को नहीं ले जाता है, वाहन लिफ्ट प्रदान करने के लिए वायुगतिकीय बलों का उपयोग करता है, स्वायत्त रूप से उड़ सकता है या दूर से संचालित किया जा सकता है, खर्च करने योग्य या पुनर्प्राप्त करने योग्य हो सकता है, और एक ले जा सकता है घातक या गैरघातक पेलोड'।

यूएवी एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर सैन्य उपयोग के मामलों में लागू होता है।

हथियार वाली मिसाइलों को आमतौर पर यूएवी नहीं माना जाता है क्योंकि वाहन स्वयं एक युद्ध सामग्री है, लेकिन कुछ प्रकार की प्रोपेलर-आधारित मिसाइलों को अक्सर जनता और मीडिया द्वारा 'कामिकेज़ ड्रोन' कहा जाता है। इसके अलावा, यूएवी का रिमोट नियंत्रित मॉडल विमान से संबंध स्पष्ट नहीं है, उद्धरण वांछित यूएवी में रिमोट नियंत्रित मॉडल विमान शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ न्याय क्षेत्र अपनी परिभाषा आकार या वजन पर आधारित करते हैं; हालाँकि, यूएस एफएए आकार की परवाह किए बिना किसी भी चालक रहित उड़ान शिल्प को यूएवी के रूप में परिभाषित करता है। उद्धरण वांछित एक समान शब्द दूर से संचालित हवाई वाहन (आरपीएवी) है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958